needs of the passengers. The Kannur Airport which started operations on December 9, 2018, handled one million passengers within the first ten months, operated 50 daily services and 65 international services per week and was among the top ten airports in India, used by most international passengers in August and September, 2021. Yet, recently, there has been a sharp decline in the number of passengers and operating airlines. To increase the revenue of the airport and make it profitable, more flight services were necessary. As of now, there are few direct airline services from the airport. There is not even a single direct flight that connects Kannur Airport with New Delhi. The airport serves 4 districts of Kerala - Kannur, Kasaragod, Wayanad and Kozhikode and caters to passengers from Karnataka and Tamil Nadu. The development of the airport would certainly contribute to the economic growth and industrial development of the region. If the airport gets 'Point of Call Status', many international airlines can start direct services from Kannur. This will be a huge relief to the airport and the needy passengers. The strategic location and state-of-the-art infrastructure offer enormous opportunities for the airport to act as a vital connectivity point. Enhanced connectivity would reflect in the growth of tourism and related industries also. Therefore, I request the concerned Minister to address these issues and save the airport from an existential crisis. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sandosh Kumar P: Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala) and Shri Haris Beeran (Kerala).

Demand for infrastructure development, regular staffing and digitisation of post offices in Odisha

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): मैं ओडिशा में, विशेष रूप से ग्रामीण पंचायतों में डाकघरों के बुनियादी ढांचे के विकास, नियमित स्टाफिंग और डिजिटलीकरण की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कई डाकघर वर्तमान में अपर्याप्त सुविधाओं के साथ काम कर रहे हैं। अकसर कर्मचारियों की कमी और पुरानी प्रणाली के कारण सेवा वितरण प्रभावित हो रहा है। बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, लगातार स्टाफिंग सुनिश्चित करने और डाक सेवाओं की दक्षता और पहुँच में सुधार के लिए आधुनिक डिजिटल प्रणालियों को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, डाकघर के संचालन को बढ़ाने से स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, मनीऑर्डर, टिकट बिक्री, राजस्व टिकट, सरकारी वित्तीय

योजनाएँ और बीमा उत्पादों जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान में सुविधा होगी। इससे न केवल सेवा पहुँच में सुधार होगा, बल्कि सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण समुदायों को बहुत लाभ होगा। मैं संबंधित मंत्री के ध्यान में लाने का आग्रह करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के लिए इसे अत्यंत तत्परता से संबोधित किया जाए। आपका त्वरित हस्तक्षेप डाक सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय रूप से सुधार करेगा और ग्रामीण निवासियों की आर्थिक और सामाजिक भलाई का समर्थन करेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Muzibulla Khan: Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu) and Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Now, Dr. Bhim Singh. He was not here earlier. But he has sent a request that he is back.

Demand for establishment of Extremely Backward Classes Finance and Development Corporation

डा. भीम सिंह (बिहार): महोदय, पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसमें आपसी गैर बराबरी भी काफी है। कुछ जातियां अत्यंत ही पिछड़ी हुई हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनता में अधिकांश मूलत: खेतिहर मजदूर, काश्तकार, दस्तकार, शिल्पकार, पशुपालक तथा समाज की सेवा करने वाले लोग शामिल हैं। विज्ञान की प्रगति तथा कल-कारखानों की स्थापना से ग्रामों के दस्तकार तथा शिल्पकार प्राय: बेकार हो गये हैं। जिन चीजों को वे अपनी कला कौशल से बनाते थे, उन्हें अब मशीनें बनाने लगी हैं। वे अकुशल मजदूर बन गये हैं। कृषि पर उनकी अधिक आश्रितता बढ़ गयी है, साथ ही उनकी बेरोजगारी बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि तथा कृषि पर अधिक आश्रितता बढ़ने से खेती भी अब कम होती जा रही है। तात्पर्य यह है कि सदियों से चली आ रही कठोर एवं जटिल सामाजिक व्यवस्था के शिकार पिछड़े वर्ग के इन लोगों को विज्ञान की प्रगति तथा कल-कारखानों की स्थापना ने बेरोजगार बनाकर आर्थिक रूप से पंगु बना दिया है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि पिछड़े वर्गों के लोगों की हालत सुधारने तथा इनके ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग धन्धों के विकास के लिए सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को सुदृढ़ करे और एक नए अत्यंत पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना करे, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के उत्थान के काम को अपने हाथ में ले, ताकि इस वर्ग का आर्थिक विकास हो सके।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Dr. Bhim Singh: Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Anil